

अपने अधिकार

एक गाइड बुक, आम लोगों के लिए



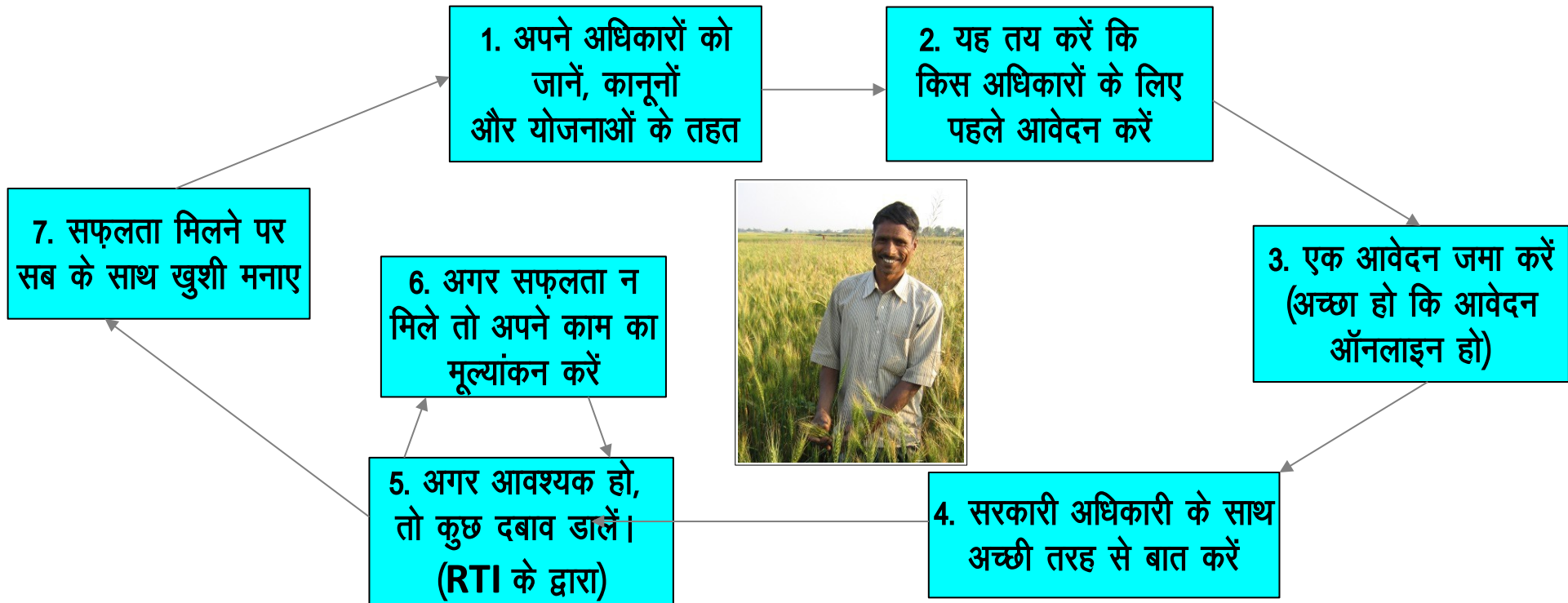
अक्टूबर 2021

7 कदम एक समुदाय को बेहतर बनाने के लिए

यह छोटी किताब आम इंसान के जीवन और उनके समुदाय को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है। सरकार ने हम सभी के लिए बहुत सारी सुविधाएं बनाई हैं। यह सुविधाएं मिलना सब लोगों का अधिकार है चाहे वे गांव, शहर या बस्ती में रहते हैं। लेकिन यह सुविधाएं आम इंसान तक नहीं पहुंच पाती हैं क्योंकि

- बहुत से लोग अपने अधिकारों को नहीं जानते ,
- बहुत से लोगों के पास प्रयाप्त दस्तावेज नहीं होते ,
- अक्सर लोगों के पास आवश्यक आवेदन शुल्क नहीं होता है ,
- कुछ सरकारी अफसरों रिश्वत माँगते है , या
- कभी-कभी लोग सरकारी अफसरों के पास जाने से डरते हैं।

इसलिए सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आम लोग दलाल के पास जाने को मजबूर होते हैं और पैसा देते हैं जबकी सुविधाएं मुफ्त होने चाहिए । यह किताब 7 कदमों में दर्शाती है कि आप और आपके साथी कैसे इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं: दलाल व रिश्वत के बिना । यह 7 कदम इस प्रकार हैं :



1. अपने अधिकारों को जानो (अक्टूबर 2021 को)

मुद्दा	आपके अधिकार (कानून, जो सबसे मजबूत अधिकार, लाल रंग में) (योजना, कानून से कम मजबूत, पर अच्छा है, काला में) वेबसाइट जनकारी नीले रंग में लाभ का विवरण	आवेदन कहाँ आवेदन करना है, शुल्क, ज़रूरी दस्तावेज़	कितना मुश्किल (आसान, मध्यम या मुश्किल) लगभग समय अवधि	कार्यालय जहाँ शिकायत कर सकते
खाना				
1. खाद्य सुरक्षा 	कानून: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें (See Sec 3(1) and Schedule 1) 'प्रधान्य परिवार' के प्रति व्यक्ति को 5 किला अनाज प्रति महीना रु 2 गेहूं, रु 3 चावल 35 किलो प्रति बहुत गरीब परिवार को प्रति महीना योजना: एक राष्ट्र एक राशन कार्ड वेबसाइट यहाँ क्लिक करें	कहाँ: स्थानीय खाद्य एवं आपूर्ति विभाग या अपने स्थानीय सी एस सी पर शुल्क: रु 5 से 45 दस्तावेज़: (यहाँ देखें) आधार (या पहचान और पते के अन्य प्रमाण), आय प्रमाण पत्र (बीपीएल के लिए), फोटो।	मध्यम 1 महीना	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का राज्य प्रमुख कार्यालय
2. आँगनवाड़ी 	कानून: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें (See Sec 5(1)a) बच्चों (6 साल से कम) के लिए, एक आँगनवाड़ी जिसमें अच्छे भोजन की व्यवस्था होती है	कहाँ: स्थानीय महिला एवं बाल विकास कार्यालय शुल्क: शून्य दस्तावेज़: 3 से 6 वर्ष के 40 बच्चों की सूची के साथ	मुश्किल से 6 महीने	महिला एवं बाल विकास विभाग का राज्य प्रमुख कार्यालय
3. मध्यान्तर भोजन 	कानून: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें (See Sec 5(1)b) कक्षा 8 तक के हर बच्चे को स्कूल में हर दिन (200 दिन साल में) अच्छा खाना	कहाँ: स्थानीय स्कूल प्रिंसिपल के पास शुल्क: शून्य दस्तावेज़: कुछ नहीं	मध्यम 1 महीना	मिड डे मील ऑथोरिटी का राज्य प्रमुख कार्यालय

मुद्दा	आपके अधिकार (कानून, जो सबसे मजबूत अधिकार, लाल रंग में) (योजना, कानून से कम मजबूत, पर अच्छा है, काला में) वेबसाइट जनकारी नीले रंग में लाभ का विवरण	आवेदन कहाँ आवेदन करना है, शुल्क, ज़रूरी दस्तावेज़	कितना मुश्किल (आसान, मध्यम या मुश्किल) लगभग समय अवधि	कार्यालय जहाँ शिकायत कर सकते
आय				
1. मनरेगा 	कानून: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना अधिनियम 2005 वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (See Sec 3(1)) हर ग्रामीण परिवार को हर वर्ष 100 दिन रोजगार कम से कम 190 रुपये प्रति दिन (यहां देखें)	कहाँ: सीनीय ग्राम पंचायत शुल्क: शून्य दस्तावेज़: आधार	मध्यम 2 महीने	ग्रामीण विकास विभाग का राज्य प्रमुख कार्यालय
2. पेंशन 	योजना: राष्ट्रीय समाज सहायता योजना वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (See page 6) 60 वर्ष से अधिक (बी पी एल) वृद्धा के लिए कम से कम रु 200 पेंशन 40 से 79 वर्ष (बी पी एल) वृद्धजनों के लिए कम से कम रु 300 पेंशन बहुत से राज्य में रु 500 या उससे अधिक हैं	कहाँ: कुछ राज्यों में ऑनलाइन या सी एस सी पर व्यक्ति में तहसील या समाज कल्याण वभाग में शुल्क: शून्य दस्तावेज़: (फॉर्म यहां देखें) आधार, बैंक खाता, आय प्रमाणपत्र: (विधवा के लिए 2 लाख से कम, वृद्धावस्था विकलांगता के लिए 56,000 से कम)	मध्यम 3 महीने	समाज कल्याण विभाग राज्य का राज्य प्रमुख कार्यालय
3. बच्ची के लिए पैसे 	योजना: बालिका समृद्धि योजना वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें सरकार लड़की के जन्म के वक्त, परिवार के खाते में रु500 जमा करती हैं। सिर्फ पहली दो लड़कियों के लिए लागू शिक्षा के हर कदम पर, राशि बढ़ती रहती है लड़की 18 साल तक शादी ना होने पर, पैसा निकाल सकते हैं।	बालिका समृद्धि योजना कहाँ: स्थानीय आंगनवाड़ी शुल्क: शून्य दस्तावेज़: आधार, बैंक खाता, जन्म प्रमाणपत्र, बीपीएल राशन कार्ड, आय प्रमाणपत्र, फोटो।	मध्यम 1 महीना	महिला एवं बाल विकास विभाग का राज्य प्रमुख कार्यालय
4. जीवन बीमा 	योजना: राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (See page 6) रु20,000 (बी पी एल) परिवार जिसके कमाने वाला की मृत्यु हो गई	कहाँ: स्थानीय समाज कल्याण विभाग शुल्क: शून्य दस्तावेज़: (फॉर्म यहां देखें) आधार, बैंक खाता, आय प्रमाणपत्र, कमाने वाले का मृत्यु प्रमाण पत्र	मुश्किल 3 महीने	समाज कल्याण विभाग का राज्य प्रमुख कार्यालय
5. छोटे व्यवसाय	योजना: MUDRA वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें रु.50,000 तक का ऋण छोटे व्यवसाय के लिए	कहाँ: ऑनलाइन (यहां देखें) या स्थानीय बैंक में व्यक्ति के द्वारा शुल्क: शून्य दस्तावेज़: (फॉर्म यहां देखें) आधार (या अन्य पहचान और पता का सबूत) मशीनों खरीदने के लिए मूल्य अनुमान	मध्यम 3 महीने	बैंक जहां आपने आवेदन किया था का राज्य प्रमुख कार्यालय

मुद्दा	<p align="center">आपके अधिकार (कानून, जो सबसे मजबूत अधिकार, लाल रंग में) (योजना, कानून से कम मजबूत, पर अच्छा है, काला में) वेबसाइट जनकारी नीले रंग में लाभ का विवरण</p>	<p align="center">आवेदन कहाँ आवेदन करना है, शुल्क, ज़रूरी दस्तावेज़</p>	<p align="center">कितना मुश्किल (आसान, मध्यम या मुश्किल) लगभग समय अवधि</p>	<p align="center">कार्यालय जहाँ शिकायत कर सकते</p>
<p align="center">स्वास्थ्य</p>				
<p>1. आर. एस. बी. वाई</p> 	<p>योजना: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वेबसाइट के लिए <u>यहां क्लिक करें</u> (आयुष्मान भारत भी कहा जाता है) सबसे कमजोर परिवारों के 500 करोड़ लोगों के लिए 5,00,000 रुपये का इलाज योजना: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन वेबसाइट के लिए <u>यहां क्लिक करें</u> सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 डाक्टर होना चाहिए और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1</p>	<p>प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए कहाँ: ऑन लाइन (<u>यहां</u> पात्रता की जांच करें) यदि आप पात्र हैं, किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएं शुल्क: शून्य दस्तावेज़: आधार, राशन कार्ड</p>	<p align="center">मध्यम 1 महीना</p>	<p>स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय :gka देखें</p>
<p>2. गर्भवती एवं स्तनपान करने वाली महिलाओं</p> 	<p>कानून: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 वेबसाइट के लिए <u>यहां</u> (See Sec 4(a) and 4(b)) और <u>यहां</u> (See Sec 2) हर एक गर्भवती महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी से मुफ्त खाना मिलता है । अस्पताल में पहली बच्चे के पैदाइश होने पर, रु 5,000 मिलते हैं ।</p>	<p>कहाँ: स्थानीय आंगनवाड़ी, आशा, या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शुल्क: शून्य दस्तावेज़: कुछ नहीं</p>	<p align="center">मध्यम 1 महीना</p>	<p>ज़िला अस्पताल का सी एम ओ</p>
<p>3. टीकाकरण</p> 	<p>योजना: योजना: यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वेबसाइट के लिए <u>यहां क्लिक करें</u> सड़ बच्चे के लिए, टी बी, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, डी.पी.टी., और चेसक का टीकाकरण, मुफ्त में</p>	<p>कहाँ: स्थानीय आंगनवाड़ी, आशा, या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शुल्क: शून्य दस्तावेज़: कुछ नहीं</p>	<p align="center">आसान 1 महीना</p>	<p>ज़िला अस्पताल का सी एम ओ</p>
<p>4. टी बी इलाज</p>	<p>योजना: डोटस वेबसाइट के लिए <u>यहां क्लिक करें</u> टी बी के मरिजो के लिए, मुफ्त जांच और इलाज इलाज के दौरान पोषण के लिए प्रति माह रु500 ।</p>	<p>कहाँ: पास का कोई डोटस केंद्र शुल्क: शून्य दस्तावेज़: आधार, बैंक खाता</p>	<p align="center">आसान 1 हफ़ता</p>	<p>राज्य टीबी अधिकारी <u>यहां</u> देखें</p>
<p>5. विकलांग व्यक्ति</p> 	<p>कानून: विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 वेबसाइट के लिए <u>यहां</u> (See Sec 2(r)) क्लिक करें पेंशन कम से कम रु 300/माह यदि 40% विकलांगता, बीपीएलए, 18 साल <u>यहां</u> योजना: यूनिवर्सल डिजाबिलिटी आईडी यूआईडी, (<u>यहां क्लिक करें</u>) विकलांगता के लिए पहचान पत्र</p>	<p>पेंशन कहीं: कुछ राज्यों में ऑनलाइन (या CSC नहीं तो, व्यक्ति द्वारा तहसील या समाज कल्याण में) दस्तावेज़: यूआईडी,, आधार, फोटो, आय प्रमाण पत्र (56,000 रुपये के अंदर) यूआईडी कहीं: ऑनलाइन <u>यहां</u> फार्म के लिए <u>यहां</u> दस्तावेज़: आधार, फोटो, विकलांग प्रमाण पत्र</p>	<p align="center">मध्यम 3 महीने</p>	<p>समाज कल्याण विभाग का राज्य प्रमुख कार्यालय</p>
<p>6. मानसिक स्वास्थ्य</p> 	<p>कानून: मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 वेबसाइट के लिए <u>यहां क्लिक करें</u> मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के अच्छे और सस्ते इलाज का अधिकार (सरकारी, या सरकारी वित्त पोषित अस्पतालों में)</p>	<p>कहाँ: पास वाला सरकार (या सरकारी वित्त पोषित) मानसिक स्वास्थ्य सुविधा शुल्क: शून्य दस्तावेज़: कुछ नहीं</p>	<p align="center">मध्यम महीना</p>	<p>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का राज्य प्रमुख कार्यालय</p>

मुद्दा	आपके अधिकार (कानून, जो सबसे मजबूत अधिकार, लाल रंग में) (योजना, कानून से कम मजबूत, पर अच्छा है, काला में) वेबसाइट जनकारी नीले रंग में लाभ का विवरण	आवेदन कहाँ आवेदन करना है, शुल्क, ज़रूरी दस्तावेज़	कितना मुश्किल (आसान, मध्यम या मुश्किल) लगभग समय अवधि	कार्यालय जहाँ शिकायत कर सकते
शिक्षा				
1. स्कूल 	कानून: शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (See Sec 3, 12(b) & 25) आठवी तक बिलकुल मुफ्त शिक्षा (Sec 3) हर 35 बच्चों के लिए 1 अध्यापक होना चाहिए (Sec 25) निजी स्कूलों (जो सरकारी सहायता प्राप्त हैं) गरीबों को 25% सीटें मुफ्त में देनी चाहिए (Sec 12(b))	आम प्रवेश कहाँ: पास वाला सरकारी स्कूल दस्तावेज़: शून्य निजी स्कूल में ईडब्ल्यूएस प्रवेश कहाँ: पास वाला निजी स्कूल शुल्क: शून्य दस्तावेज़: जन्म-प्रमाणपत्र आय-प्रमाणपत्र	मध्यम 1 महीना	शिक्षा विभाग का राज्य प्रमुख कार्यालय
2. शिक्षा का लाभ 	कानून: शिक्षा का अधिकार अधिनियम वेबसाइट के लिए यहां और यहां क्लिक करें किताब और वार्दी मुफ्त है आठवी तक	कहाँ: पास वाला सरकारी स्कूल शुल्क: शून्य दस्तावेज़: ?	मध्यम 2 महीने	शिक्षा विभाग का राज्य प्रमुख कार्यालय
3. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान 	योजना: राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें सस्ती दूरस्थ शिक्षा (स्कूल जाने के बिना) सभी के लिए 12वीं तक	कहाँ: ऑन लाइन यहां क्लिक करें या स्थानीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान केंद्र शुल्क: यहां रु2,000 तक (ट्यूशन छोड़कर) दस्तावेज़: आधार, फोटो, मार्क्स शीट	आसान 1 महीना	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा का राज्य प्रमुख कार्यालय
बिजली व गैस				
1. बिजली 	सौभाग्य (बंद किया जा सकता है) वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें कनेक्शन के लिए पात्र सभी अविद्युतीकृत परिवार	कहाँ: राज्य डिस्कॉम से संपर्क करें शुल्क: राज्य से राज्य के लिए बदलता है दस्तावेज़: अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग	मध्यम 3 महीन	बिजली देने वाली कम्पनी (जिसको आपने आवेदन किया) उस राज्य का प्रमुख कार्यालय
2. गैस कनेक्शन 	योजना: उज्ज्वला 2.0 वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें हर घर जिसमें खाना पकाने की जगह अलग और पक्का स्लॉव हो उस घर को एक गैस कनेक्शन मिल सकता है। सब्सिडी वाले कनेक्शन के लिए पात्र कोई भी गरीब वयस्क महिला	कहाँ: स्थानीय इंडेन या भारत गैस से संपर्क करें शुल्क: लगभग रु.1,600 दस्तावेज़: (फॉर्म यहां देखें) राशन कार्ड, आधार, (KYC फॉर्म यहां देखें) बैंक खाता	मध्यम 15 20 दिन	इण्डेन या भारत गैस (जिसको आपने आवेदन किया) का राज्य प्रमुख कार्यालय

<p>मुद्दा</p>	<p>आपके अधिकार (कानून, जो सबसे मजबूत अधिकार, लाल रंग में) योजना, कानून से कम मजबूत, पर अच्छा है, काला में) वेबसाइट जनकारी नीले रंग में लाभ का विवरण</p>	<p>आवेदन कहाँ आवेदन करना है, शुल्क, ज़रूरी दस्तावेज़</p>	<p>कितना मुश्किल (आसान, मध्यम या मुश्किल) लगभग समय अवधि</p>	<p>कार्यालय जहाँ शिकायत कर सकते</p>
<p>गाँव सुवीधाएँ</p>				
<p>1. शौचालय/ लैट्रीन</p> 	<p>योजना: निर्मल भारत अभियान (ग्रामीण) वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें (See 6.4.6 on page 23) पक्की लैट्रीन बनाने के लिए रु 12,000 की सबसिडी योजना: स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें (See 4.4 on page 13) पक्का लैट्रीन बनाने के लिए रु 4,000 की सबसिडी</p>	<p>कहाँ: ऑन लाइन यहाँ देखें या अपने स्थानीय सी एस सी पर, नहीं तो स्थानीय ग्राम पंचायत शुल्क: शून्य दस्तावेज़: आधार, बैंक खाता, फोटो</p>	<p>मध्यम 3 महीने</p>	<p>ग्रामीण: मंत्रालय पेयजल स्वच्छता यहाँ देखें शहरी: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यहाँ देखें</p>
<p>2. खड़न्जा और नालिया</p> 	<p>योजना: ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें (See 3.2 on page 17) ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति को रु10,000 हर साल मिलते हैं गाँव के विकास, जैसे खड़न्जा, नालियों और साफ-सफाई के कार्यों के लिए</p>	<p>कहाँ: स्थानीय ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति से संपर्क करें शुल्क: शून्य दस्तावेज़: ?</p>	<p>मुश्किल 6 महीने</p>	<p>लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग का राज्य प्रमुख कार्यालय</p>
<p>3. मकान</p> 	<p>योजना ग्रामीण: प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें (see pviii (#5) & p27 (5.1.1) गरीब ग्रामीण परिवारों को घर बनाने लिए रु.1,20,000 योजना (शहरी): लाभार्थी की देख-रेख में निर्माण (बीएलसी) शहरी वेबसाइट के लिए यहाँ और यहाँ क्लिक करें (see p 10 (#7) यदि आपके पास ज़मीन है, तो निर्माण करने के लिए 2,50,000 रुपये तक का प्रावधान</p>	<p>ग्रामीण: (पी एम ए वाई) कहाँ: ऑन लाइन यहाँ देखें या सी एस सी या पंचायत या बी डी ओ या जिला डीडी ओ से शुल्क: शून्य दस्तावेज़: ? शहरी: लाभार्थी देख-रेख में निर्माण (BLC) कहाँ: ऑन लाइन यहाँ(see Citizen Assesmt) शुल्क: शून्य दस्तावेज़: प्रमाण पत्र (आय, निवास और जाति निवास), भूमि रजिस्ट्री, शपथ पत्र आदि।</p>	<p>मुश्किल 1 साल</p>	<p>ग्रामीण: ग्रामीण विकास मंत्रालय यहाँ देखें शहरी: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यहाँ देखें</p>
<p>4. भूमिहीनों के लिए भूमि</p> 	<p>योजना (शहरी): सस्ता आवास साझेदारी में (AHP) वेबसाइट के लिए यहाँ पर क्लिक करें बड़ी सब्सिडी वाला सरकारी प्लैट। आमतौर पर लॉटरी से तय होता है।</p>	<p>साझेदारी में किफायती आवास (ए एच पी) कहाँ: ऑन लाइन यहाँ(see Citizen Assesmt) या स्थानीय सी एस सी से संपर्क करें शुल्क: शून्य दस्तावेज़: आधार, बैंक खाता</p>	<p>बहुत मुश्किल 1 साल से ज्यादा</p>	<p>ग्रामीण: ग्रामीण विकास मंत्रालय यहाँ देखें शहरी: आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय यहाँ देखें</p>
<p>5. सड़कें</p> 	<p>योजना: प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना वेबसाइट के लिए यहाँ क्लिक करें (see page 1 Sec 1.2) हर गांव जिस में 500 से ज्यादा लोग रहते हैं (पहाड़ी इलाको में 250) तक पक्की सड़क।</p>	<p>कहाँ: स्थानीय लोक निर्माण विभाग से संपर्क करें शुल्क: शून्य दस्तावेज़: ?</p>	<p>मुश्किल 1 साल</p>	<p>ग्रामीण: ग्रामीण विकास मंत्रालय यहाँ देखें</p>

<p>मुद्दा</p>	<p>आपके अधिकार (कानून, जो सबसे मजबूत अधिकार, लाल रंग में) (योजना, कानून से कम मजबूत, पर अच्छा है, काला में) वेबसाइट जनकारी नीले रंग में लाभ का विवरण</p>	<p>आवेदन कहाँ आवेदन करना है, शुल्क, ज़रूरी दस्तावेज़</p>	<p>कितना मुश्किल (आसान, मध्यम या मुश्किल) लगभग समय अवधि</p>	<p>कार्यालय जहाँ शिकायत कर सकते</p>
<p>मानव अधिकार</p>				
<p>1. घरेलू हिंसा </p>	<p>कानून: घरेलू हिंसा से महिलाओं को मुक्ति अधिनियम 2005 वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (see Sec 3) किसी भी प्रकार का घरेलू हिंसा (मारना, तंग करना, खाना ना देना, धमकी देना, गाली, दहेज मांगना) सख्त मना है ।</p>	<p>कहाँ: स्थानीय पुलिस थाना से संपर्क करें शुल्क: शून्य दस्तावेज: शून्य</p>	<p>मध्यम 2 हफते</p>	<p>राज्य महिला आयोग यहां देखें</p>
<p>2. बाल मजदूरी </p>	<p>कानून: बाल श्रम अधिनियम 1986 वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (see Sec 3, 7 and schedule यहां) 14 साल से कम बच्चे से किसी भी खतरनाक काम (जैसे ढाबों, घरेलू काम, पटाखे की फैक्ट्री) में काम करवाना गैरकानूनी है। दिन में 6 घंटे से ज्यादा नहीं। शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे तक कोई काम नहीं कराया जा सकता</p>	<p>कहाँ: 1098 मुफ्त हेल्पलाइन नम्बर पर फोन करें शुल्क: शून्य दस्तावेज: शून्य</p>	<p>मुश्किल 2 हफते</p>	<p>राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यहां देखें</p>
<p>3. बाल शादी </p>	<p>कानून: बाल शादी अधिनियम 2006 वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (see Sec 2 & 11) लड़का 21 वर्ष से कम और लड़की 18 वर्ष से कम शादी गैरकानूनी है जो बाल शादी करवाता है उसके लिए सजा का प्रावधान है</p>	<p>कहाँ: 1098 मुफ्त हेल्पलाइन नम्बर पर फोन करें शुल्क: शून्य दस्तावेज: शून्य</p>	<p>मुश्किल 2 हफते</p>	<p>राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यहां देखें</p>
<p>4. तस्करी वेश्यावृत्ति </p>	<p>कानून: तस्करी वेश्यावृत्ति अधिनियम 1956 वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (see Sec 5 & 17) तस्करों को आजीवन कारावास की सज़ा भी हो सकती। (Sec 5) नाबालिग बच्ची को बाल कल्याण समिति द्वारा देख-रेख में दिया जा सकता है। (Sec 17)</p>	<p>कहाँ: स्थानीय पुलिस थाना से संपर्क करें शुल्क: शून्य दस्तावेज: शून्य</p>	<p>मुश्किल 6 महीने</p>	<p>राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यहां देखें</p>
<p>5. तस्करी बंधुआ मजदूर </p>	<p>कानून: बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें (see Sec 4) और यहां बंधुआ मजदूरी निषेध है। बंधुआ मजदूरों को कर्ज से मुक्त किया जाता है। बंधुआ मजदूरों को मुआवज़ा दिया जाता है। समाज में फिर दोबारा जोड़ना की मदद।</p>	<p>कहाँ: ज़िला विजिलेंस समिति से संपर्क करें शुल्क: शून्य दस्तावेज: शून्य</p>	<p>मुश्किल 6 महीने</p>	<p>राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग यहां देखें</p>

मुद्दा	आपके अधिकार (कानून, जो सबसे मजबूत अधिकार, लाल रंग में) (योजना, कानून से कम मजबूत, पर अच्छा है, काला में) वेबसाइट जनकारी नीले रंग में लाभ का विवरण	आवेदन कहाँ आवेदन करना है, शुल्क, ज़रूरी दस्तावेज़	कितना मुश्किल (आसान, मध्यम या मुश्किल) लगभग समय अवधि	कार्यालय जहाँ शिकायत कर सकते
कागजात				
1. आधार कार्ड	योजना: भारत आधार आयोग वेबसाइट के लिए <u>यहां क्लिक करें</u> किसी भी भारतीय निवासी के लिए मुख्य पहचान पत्र। बॉयोमीट्रिक्स जानकारी शामिल है जो कि समय-समय पर अपडेट होती है, 5 साल और 15 साल में।	कहाँ: कुछ राज्यों में जन सेवा केंद्र में या सीएससी, नहीं तो स्थानीय नामांकन केंद्र पर संपर्क करें शुल्क: नामांकन 0, अद्यतन विवरण रु 50 दस्तावेज़: फार्म <u>यहां</u> देखें। आईडी, पता और उम्र के सबूत। यदि दस्तावेज़ की कमी है, तो 'परिचयकर्ता'	आसान 1 महीना	भारत आधार आयोग UIDAI का राज्य प्रमुख कार्यालय
2. पैन कार्ड	योजना: पैन कार्ड वेबसाइट के लिए <u>यहां क्लिक करें</u> यदि आयकर का भुगतान करना अनिवार्य है गैर करदाताओं के लिए भी उपलब्ध है।	कहाँ: ऑन लाइन यहां देखें या कुछ राज्यों में जन सेवा केंद्र में या स्थानीय सी एस सी से संपर्क करें शुल्क: रु 107 दस्तावेज़: आधार, 2 फोटो	आसान 1 महीना	आयकर विभाग का राज्य प्रमुख कार्यालय
3. मतदाता पहचान पत्र	योजना: भारत का चुनाव आयोग वेबसाइट के लिए <u>यहां क्लिक करें</u> हर भारतीय जिसकी उम्र 18 से ऊपर है को पहचान पत्र मिलें। फिर उस व्यक्ति को मतदाता पहचान पत्र मिल सकता है।	कहाँ: ऑन लाइन यहां देखें या कुछ राज्यों में जन सेवा केंद्र में या स्थानीय सी एस सी से संपर्क करें शुल्क: शून्य दस्तावेज़: फॉर्म 6, आईडी, पता और उम्र (यदि 21 साल से कम है) के सबूत	मध्यम 1 महीना	राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी
4. बैंक खाता	योजना: प्रधानमंत्री जन धन योजना वेबसाइट के लिए <u>यहां क्लिक करें</u> 10 साल से अधिक का कोई भी व्यक्ति बैंक खाता खोल सकता है।	कहाँ: कोई भी बैंक से संपर्क करें शुल्क: PMJDY शून्य, नहीं तो रु500-1,000 दस्तावेज़: यहां आधार, 2 फोटो	मध्यम 15 दिन	बैंक जिस पर आपने आवेदन किया, उसका राज्य प्रमुख कार्यालय
5. जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र	कानून: जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 वेबसाइट के लिए <u>यहां क्लिक करें</u> (see Sec 8 & 12) भारत में पैदा हुए किसी भी बच्चे के लिए जन्म प्रमाण पत्र भारत में मरने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र	कहाँ: अगर जन्म पंजीकृत हो, तो नगर निगम, अगर पंजीकृत नहीं हो, तो एसडीएम से संपर्क करें शुल्क: शून्य (सरकारी अस्पताल), रु100 (निजी) दस्तावेज़: जन्म प्रमाण पत्र सरकारी अस्पताल, शून्य निजी में, तो आधार और निर्वहन पर्ची	मध्यम 1 महीना	ज़िला मैजिस्ट्रेट
6. जाति प्रमाण पत्र	योजना: जाति प्रमाण पत्र वेबसाइट के लिए <u>यहां क्लिक करें</u> अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग भारतीय के लिये, प्रमाण पत्र	कहाँ: उपमंडल मजिस्ट्रेट के पास जाएं शुल्क: जन सेवा केंद्र में रु300 दस्तावेज़: आधार, जाति पर शपथ पत्र	मध्यम 3 महीने	ज़िला मैजिस्ट्रेट
7. श्रम कार्ड	कानून: भवन निर्माण अन्य निर्माण कामगार अधिनियम 1996 वेबसाइट के लिए <u>यहां क्लिक करें</u> (see Sec 12) निर्माण उद्योग में कोई भी, 18-60 साल है और वास्तव में पिछले 12 महीनों में 90 से अधिक दिनों के लिए काम किया हो उसको श्रम कार्ड मिल सकता है।	कहाँ: कुछ राज्यों में ऑन लाइन जैसे यू पी यहां शुल्क: ? दस्तावेज़: <u>gka</u> पहचान, आयु और रोजगार का प्रमाण	मध्यम 1 महीना	श्रम विभाग का राज्य प्रमुख कार्यालय

2. किस अधिकार के लिए आवेदन करें ?

एक जन के अधिकार: कुछ अधिकार जैसे पेंशन या राशन कार्ड से, सिर्फ एक ही व्यक्ति को फायदा होता है और उनका मिलना थोड़ा आसान भी है। अगर आप भी किसी ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं तो आप इस किताब के 3 – 7 कदम द्वारा अपनी समस्या हल कर सकते हैं। फिर आप भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। उस से पैसा न लें।

समुदाय के अधिकार: इसके अलावा कुछ समस्याएं, जैसे बिजली या साफ पानी की कमी, पूरे गाँव या बस्ती पर असर करती हैं। इन समस्याओं को हल करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए पूरे समुदाय को मिल कर काम करना होगा और साथ मिलकर इन्हे सुलझाना होगा। अगर आपके गाँव या बस्ती में ऐसी कोई समस्या है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की बैठक करे और मद्दे पर चर्चा करे। याद रखे इस मीटिंग में :

- **सभी की बात सुने:** आमतौर पर सिर्फ बड़े बड़े लोग ही ऐसी बैठकों में उपस्थित रहते हैं, मगर आप सभी लोगों को पूरा महत्व दे। इसलिए कोशिश करे की बैठक में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, विकलांग और गरीबों की उपस्थिति हो।
- पहले से ही आप **किसी ऐसे व्यक्ति को चुन** ले जिसकी समुदाय में अच्छी पकड़ हो और सभी लोग उसकी सुनते हो और इज्जत करते हो, इससे आपको बैठक को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
- **सब लोगों की बातें ध्यान से सुने:** जो भी उन्होंने बोला, आप उसे दोबारा दोहराए ताकि वह ये जान पाए कि आप उनकी बातें समझ गए हैं।
- **किसी को ज्यादा न बोलने दे:** वरना दूसरे लोगों को बोलने का मौका नहीं मिल पाएगा। अगर कोई ज्यादा बोल रहा है, उस की बात और भी ज्यादा दोहराओ, ताकि वह जान ले कि आप उसे सुन रहे हैं और वह अपने आप खामोश हो जाए।
- उम्मीद है कि फैसला हो जाएगा कि **किस समस्या को पहले हल करें**। अगर जरूरी हो, वोट कर सकते हैं, मगर वोट हारने वाले निराश हो सकते हैं। बेहतर हो कि समझौते से सब लोग – छोटे – बड़े – उस समस्या को पहले हल करने के लिए तैयार हो।

उस समस्या को चुने जो :

- आपके जिले में किसी दूसरे गाँव या बस्ती ने इस ऐसी समस्याओं को हल किया है।
- हल करने में कम पैसा लगेगा।
- हल करने में कम समय लगेगा।
- हल करने में कोई दुश्मन न बनेंगे। (जैसे की जुआ, शराब इस तरहों की चीजों पर रोक लगाने से दुश्मन बन सकते हैं।)
- काफी जरूरी है: जैसे एक नई सड़क से पहले, एक बहुत बीमार रोगी का इलाज करवाँ क्योंकि यह अधिक जरूरी है।
- ज्यादा लोगों पर असर पड़े।
- हल करने के लिए लोगों में काफी जोश हों।



3. अधिकार मिलने के लिए आवेदन करना

अगर हो सके है, तो ऑन लाइन आवेदन करें ताकि रिश्तत मांगने का मौका न हो। कई गांवों में एक कॉमन सर्विस सेंटर (यहां देखें) होता है, जहां आप कुछ पहचान दस्तावेजों और अन्य योजनाओं के लिए ऑन लाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार, राजस्थान, यूपी और एमपी में आप स्थानीय जन सेवा केंद्र का इस्तेमाल कर सकते हैं (यहां देखें)। कुछ आवेदन विशेष फॉर्म की आवश्यकता होती है जोकि दफ्तरों में उपलब्ध होते हैं।

अगर फॉर्म न मिल तो, खाली कागज पर अपना आवेदन लिखे। आपके आवेदन में जरूर निम्नलिखित 4 बातें होनी चाहिए :

- 1 **अपनी समस्या को साफ बताइए।** जैसे: आपके गाँव में आंगनवाड़ी नहीं है। अगर समस्या का फोटो भी हो, तो उसे भी चिपका दीजिए। इससे आवेदन और भी अच्छा बनेगा।
- 2 **अपने अधिकार,** और किस कानून या योजना से यह अधिकार मिलता है (तलिका में हरे खाने को देखिए)। जैसे: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 5 (1) (ए) के तहत, यहां सरकार को 6 महीने से 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को आंगनवाड़ी प्रदान करनी चाहिए।
- 3 **अपनी माँग साफ बताइए यानी** आपको क्या चाहिए, कब तक, जैसे: आप चाहते हैं कि 30 जून 2021 तक एक आंगनवाड़ी की स्थापना हो। (तलिका में नीले खाने को देखिए)
- 4 **दबाव।** साफ बताइए कि अगर आपका काम पूरा ना हो तो आप क्या दबाव डालेंगे। जैसे: अगर 30 जून 2021 तक आपके गाँव में आंगनवाड़ी न हो, तो हम आर टी आई डालेंगे।

अपने आवेदन की एक कॉपी मुख्य कार्यालय (बड़े अफसर) (तलिका में गुलाबी खाने को देखिए) को भी भेज देना। फिर शायद छोटा अफसर बात मान कर जल्दी काम कर दे।

आवेदन लिखकर आप सही सरकारी दफ्तर को डाक से भेज सकते हैं (तलिका में पीले खाने को देखिए)। अगर आप यह करें तो, रजिस्टरड पोस्ट के द्वारा ही अपना आवेदन भेजें, और रीसीट सुरक्षित रख ले, ताकि आप दिखा सकते हैं कि किस दिन यह भेजा गया था। आवेदन का नमूना नीचे दिया गया है:

सेवा में
समेकित बाल विकास योजना
ज़िला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश
1 मई 2021

शिवारामपुर के लिए आंगनवाड़ी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 5 (1) (ए) के तहत

महोदय,

मैं शिवारामपुर, ज़िला फतेहपुर का निवासी हूँ। मैं सम्मानपूर्वक निम्नलिखित बताता हूँ: -

- 1 हमारे गाँव की आबादी 2,350 है, जिनमें से 6 महीने से 6 साल के बीच की उम्र के 272 बच्चे हैं। अभी तक हमारे गाँव में कोई आंगनवाड़ी नहीं है। मैं अपने गाँव में इस उम्र के बच्चों की एक सूची संलग्न की है, साथ में उनकी एक फोटो भी है।
- 2 मैं जानता हूँ कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 5 (1) (ए) के तहत, (यहां देखें) सरकार को 6 महीने से लेकर 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को आंगनवाड़ी प्रदान करनी चाहिए।
- 3 इसलिए मैं अपने गाँव के लिए कई आंगनबाड़ियों के लिए आवेदन करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि ये आंगनबाड़ियां 30 जून, 2021 तक शुरू हो जाएं।
- 4 अगर 30 जून, 2021 तक आंगनबाड़ियां न हो, तो मैं आर टी आई डालूंगा, मालुम करने के लिए कि मेरा आवेदन को क्या हुआ।

रामेश कुमार,

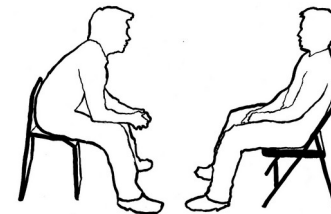
मकान न 6, गली न 7, शिवारामपुर गाँव, ज़िला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, टेलीफोन 9750 478 598

हमने यह आवेदन उत्तर प्रदेश का समेकित बाल विकास योजना का प्रधान कार्यालय को भी भेजा है।

4. सरकारी अधिकारी के साथ अच्छी तरह से बात करें

कभी कभी, सरकारी अधिकारी से मिलना, या आवेदन देने के लिए, या उसकी प्रगति पर जांच करने के लिए, ज़रूरी होता है। यदि आप सरकारी अधिकारी से मिलें, तो ये बातें पर ध्यान रखें: **मीटिंग से पहले अच्छी तैयारी करो**

- अपने साथ किसी आस-पड़ोस के व्यक्ति को साथ ले कर जाए। यदि वह अफसर घूस मॉगता है तो वह साथी चश्मदीत गवाह बन सकता है।
- मिलने का समय तय करने के लिए, जाने से पहले फोन करे ताकि आपका समय बर्बाद न हो।
- अच्छे कपड़े भी पहन कर जाए, ताकि आप दिखा सके कि आप कोई है।
- डायरी या कॉपी और पेन साथ ले जाए, ताकि आप काम की तारीख व कोई कही हुई बात लिख सके।
- हर कागज़ की 2 फोटोकॉपी ले जाए, एक अफसर को देने के लिए व एक साइन करके वापस अपने पास रखने के लिए।
- जो भी कागज़ात, दस्तावेज़ या चिट्ठी जो जमा करनी है (तलिका में पीले खाने को देखिए), उसकी असली वाली और उसकी 2 फोटोकॉपी ले जाए ताकि आप असली वाली अफसर को दिखा सके लेकिन उसे असली कॉपी न दे।
- अफसर आपको कई बहाने दे सकते हैं! इसके लिए तैयार रहें, और बहाने सुनकर आप गुस्सा न हो।
- अपने अधिकार (तलिका में हरे खाने को देखिए) को जान ले। अगर अधिकार मिलने के लिए कोई फीस, लगती है, तो उस के लिए पैसे ले कर जाए।
- दफ़्तर का नाम और पता जान लीजिए (तलिका में पीले खाने को देखिए), ताकि समय पर पहुंचें।
- पहले से ही सोच कर जाइए कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाए, तो हमें और किस किस तरह दबाव डालना है।
- अधिकारी के ऊपर बड़े अधिकारी का नाम जानें (तलिका में गुलाबी खाने को देखिए), ताकि आप दबाव डाल सकें।
- पहले से सोच ले कि कौन क्या बात करेगा, ताकि सब लोग एक साथ न बोलने लगे।



मीटिंग के दौरान

- अपना परिचय दे। अगर हो सके, उनका नाम, पद और फोन नम्बर भी पूछ कर लिख लेना।
- अपना आने का कारण साफ़ शब्दों में बताए और उन्हें पहले ही बोल दे कि आप उनका ज़्यादा समय नहीं लेंगे।
- जो भी कागज़ात या आवेदन देना है तो अपनी एक कॉपी पर "रीसीव्ड" मोहर ज़रूर लगवाए।
- यदि अफसर बहाने बनाए तो खामोश रहे, ऊची आवाज़ में न बोले। अगर झगड़ा होता है तो इसमें आपका ही नुकसान होगा।
- जो कुछ भी अफसर आपसे कहते हैं, उसको दोहराना। उम्मीद है कि फिर वो अपनी अकारण प्रतिक्रियाएँ खुद महसूस करेगा।
- अगर कर्मचारी कहते हैं कि "बाद में देखेंगे" तो तारीख ज़रूर तय कीजिए, और वह तारीख अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
- साफ़-साफ़ बताए कि अगर अपना काम नहीं होता है तो आप और क्या दबाव डालेंगे (6वीं कदम देखो) और कब तक, मगर गुस्सा न हो।
- जाते समय शुक्रिया ज़रूर कहिये। ऐसे कहने से, उम्मीद है कि अगली बार वह अफसर आपकी मदद करेंगे।

अगर कर्मचारी रिश्वत (धूस) या चाय पानी मांगे

- उससे पूछे कि इस पैसे के बारे में कहाँ लिखा है, ताकि उसकी गलती पर रोशनी पड़े ।
- उससे कहें कि आप पैसे देने को तैयार हैं अगर वो आपको लिखित पर्ची दे – वह कुछ भी लिखने से डर जाएगा ।
- उसकी मांग को जोर से दोहराएँ ताकि आस-पास के लोग सुन सकें और उसे शर्म आए ।
- अगर वो फिर भी मांगे तो उसके सामने उसके बारे में पूरी जानकारी लिखें– नाम, पद, चेहरा, वह कहाँ बैठता है वगैरा-वगैरा ।
- अगर फिर भी धूस मांगे तो उसकी शिकायत उससे बड़े अफसर से लिखित रूप में करें ।

मीटिंग के बाद, लिख लेना ताकि याद रहे:

- मीटिंग की तारीख और समय,
- किससे मिले, उसके नाम और पद,
- क्या नतीजा हुआ मीटिंग में ।
- जो भी कोई कागजात दिए या लिए है उसकी एक अलग फाइल बना ले और ठीक से रख लें ।
- जो भी काम सरकारी कर्मचारी ने कहा कि वह करेगा, और कब तक ।
- अगर सरकारी कर्मचारी अपना काम न करे, तो आप क्या करेंगे, और कब तक ।



5. अगर ज़रूरत पड़े तो अधिकारी पर थोड़ा दबाव डाले

याद रखें कि आवेदन पत्र में, आपने लिखा है कि आप कब तक कार्रवाई करना चाहते थे । सड़क बनाने, आधार कार्ड बनाने या आंगनबाड़ियों शुरू करने में समय लगता है । सरकारी अधिकारियों को काफी लोगों का काम करना है । इसलिए दबाव डालने से पहले थोड़ा सा इंतज़ार करें (तलिका में नीले खाने को देखें) । जब उसका समय खत्म होने वाला हो, तब अधिकारी को एक फोन कर दे, उसे समय सीमा की याद दिलाने के लिए और उस पर थोड़ा दबाव रखने के लिए! अगर उचित समय का इंतज़ार करने के बाद आपका काम नहीं हुआ है, तो आप उस सरकारी कर्मचारी पर थोड़ा और दबाव डालें ।

दोबारा से सामुदायिक मीटिंग बुलाएँ और चर्चा करें कि, किन तरीकों से दबाव डाला जा सकता है । कई अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे:

- हो सके तो :gka ऑन लाइन अपने आवेदन की स्थिति की जांच करें ।
- एक बार फिर से उस अधिकारी से शिकायत करें जहां आपने आवेदन किया था
- सरकार की शिकायत करने का तरीका इस्तेमाल करें (यहां देखें)
- बड़े अफसर से शिकायत करें (तलिका में गुलाबी खाने को देखिए)
- उस विभाग में जहां पहले आवेदन दिया था, एक आर. टी. आई. डालें, या ऑन-लाइन (यहां देखें), या लिखित रूप में । नीचे आर. टी. आई. का नमूना देखिए ।
- एक गैर सरकारी संगठन, जो उस क्षेत्र में काम करती हो , (जैसे जस्टिस वेंचर्स इंटरनेशनल) उनसे संपर्क करें ।
- यदि आप किसी मीडिया वाले को जानते हैं तो उससे सम्पर्क कीजिये : वह आपकी पुरे मामसे की कहानी लिखेगा ।

(आर टी आई का नमूना केवल मोटे अक्षरों को बदलना है)

सेवा में
जन सूचना अधिकारी
समेकित बाल विकास योजना
फतेहपुर जिला
उत्तर प्रदेश

1 जुलाई 2021

विषय: आर टी आई अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन
शिवारामपुर के लिए आंगनवाडी के सम्बंध में जानकारी हेतु

महोदय,

- 1 मैंने अपने गाँव शिवारामपुर के लिए आंगनवाडी के लिए 1 मई 2021 को आवेदन किया था। उस आवेदन की एक प्रति संलग्न है। मेरे आवेदन पर अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए कृपया करके निम्नलिखित जानकारी दे।
- 2 आपके विभाग के नियम और उपनियम के अनुसार, पक्की सड़क बनाने हेतु कितना समय लगना चाहिए ?
- 3 मेरे आवेदन पर हुई दैनिक प्रगति उपलब्ध कराई जाए। इस अवधि में मेरा आवेदन जिस अधिकारी के पास था उसका नाम और पद उपलब्ध कराया जाए। उस अधिकारी के पास कितने समय तक मेरा आवेदन रहा और उस अवधि में उसने उस पर क्या कार्यवाही की ?
- 4 जिस अधिकारी/कर्मचारी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और देरी का कारण बना, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? ये कार्यवाही कब तक की जाएगी ?
- 5 शिवारामपुर अपनी आंगनवाडी कब तक प्राप्त कर पाएगी ?

मैं इस आर टी आई के साथ आवेदन शुल्क (रु. 10) अलग से जमा कर रहा हूँ।

अगर आपको लगता है कि ये सूचना आपके विभाग से सम्बंधित नहीं है तो कृपया आर टी आई अधिनियम 2005 के अनुच्छेद का 6(3) अनुपालन करें। आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार कृपया अपने विभाग प्रथम अपील अधिकारी का विवरण (नाम व पद) अनुरोध किए गए उक्त जवाब के साथ हमें प्रदान करने की कृप्या करें ताकि मैं जरूरत पड़ने पर प्रथम अपील दायर कर सकूँ।

धन्यवाद

रामेश कुमार,

मकान न 6, गली न 7,

शिवारामपुर गाँव, जिला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश,

टेलीफोन 9750 478 598

हमने यह आर टी आई उत्तर प्रदेश समेकित बाल विकास योजना को भी भेजी है। (तलिका में गुलाबी खाने को देखिए)

6. कदम: अपने काम का मूल्यांकन!

यदि, दबाव लागू करने के बाद, आप अभी भी सफल नहीं हुए हैं तो:

- अपने साथियों के साथ बैठो और चर्चा करो, कि आपने अबतक क्या अच्छा किया है, और क्या बेहतर कर सकते थे ।
- यह देखें कि क्या आप एक अलग तरह का दबाव लागू कर सकते हैं, या आपको किसी की मदद की आवश्यकता है।
- अधिकार प्राप्त करने के लिए एक नई योजना बनाएं।
- नई योजना पर काम करें। हम इसे एक एक्शन-रिफ्लेक्शन चक्र कहते हैं: योजना बनाना, मूल्यांकन करना, योजना बनाना, मूल्यांकन करना, आदि

7. सफलता मिलने पर सब के साथ खुशी मनाओ

उम्मीद है कि इन 7 कदमों को पूरा करने से आप को आखिर में अपने अधिकार मिल ही जाएंगे, और सब को उस के फायदे मिलेंगे। अगर यह हो जाए तो:

- सब लोग जिन्होंने मदद की उन के साथ खुशी मनाओ । सब को समोसे और मिठाई खिलाओ !
- जिस अफसर ने अच्छा काम किया, उनको शुक्रिया जरूर कहिए। उसको अच्छा भी लगेगा, और शायद वह बाद में और मदद करेगा।
- दूसरे गाँव व बस्ती वालों को अपनी सफलता के बारे में जरूर बताए और अगर वह भी ऐसे ही कोशिश करना चाहते हैं, उनको भी मदद करें।
- दुबारा सब लोगों के साथ मिल कर फैसला कीजिये कि अब अगली कौनसी समस्या को ले ताकि उस समस्या के साथ आप फिर से वैसे ही शुरूआत करे । यानी आप पहले कदम से काम फिर शुरू करे ।



सफलता की कहानियाँ

राजू को विकलांगता पेंशन मिलती है

राजू, एक रेलवे ट्रैक के किनारे से एक झोंपड़ी में रहता है। 5 बच्चों का पिता होने के नाते, वह कबाड़ी का काम करता है जिससे वह ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता है। एक पर्याप्त शारीरिक विकलांगता होने के बावजूद—उसके बाये पैर में फालिज है और पैर मुड़ा हुआ है—वह अपने काम के लिए कई किलोमीटर साइकिल से जाता है। जब हमारे समुदाय के कार्यकर्ता, राजू से मिले तो राजू ने उनके लिए विकलांगता पेंशन के लिए आवेदन करने को कहा। वह पहले व्यक्ति थे, जिसके लिए समुदाय के कार्यकर्ता ने आवेदन किया था, इसलिए सिस्टम सीखने में कुछ समय लगा—उनके दस्तावेजों की फोटो लेना, उन्हें ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपलोड करना और जिला विकलांग कल्याण कार्यालय में हार्ड कॉपी जमा करना। कई महीनों के इंतजार के बाद राजू को नवंबर 2020 में पहली किस्त मिली! 500 रुपये (USD \$7) प्रति माह ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ तो है। राजू की सफलता के बाद से कई अन्य लोग विभिन्न प्रकार की पेंशन (विकलांगता, विधवा और वृद्धावस्था) के लिए आवेदन करने की मांग करते हुए आगे आए हैं।

रूबी एक गैस कनेक्शन हो जाता है

रूबी, 24 साल, एक रेलवे ट्रैक के किनारे से एक झोंपड़ी में रहती है उनकी 3 साल की बेटी और उनके पिताजी के साथ। वह घर के अंदर एक लकड़ी के चुल्हे पर खाना पकाती थी, जो उसके लिए कष्ट दायक और समय लेने वाला था, और उसकी बेटी और बुजुर्ग पिता के लिए साँस लेने में मुश्किल होती थी। वह गैस कनेक्शन के लिए आवेदन करने के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन पैन कार्ड और बैंक खाता (एक सरकारी गैस कनेक्शन के लिए आवश्यकताएं) और पैसे नहीं थे। हम उसे दोनों एक पैन कार्ड और एक बैंक खाते के लिए आवेदन करने में मदद की, और फिर स्थानीय गैस वितरक को उसके दस्तावेजों की फोटोकॉपी जमा करवाई, साथ ही साथ थोड़े पैसे की मदद भी की (डिपोजिट के लिए)। अब रूबी एक साफ, सस्ता और अधिक सुविधाजनक ईंधन पर खाना पकाने के साथ—साथ समय, पैसे, और उसके फेफड़ों को बचाती है।



सविता की जान टीबी से बचाई जाती है

28 साल की सविता को कई महीनों तक सिर दर्द और जी मचलने से काफी पीड़ित रही। उसे मार्च 2020 में कोविड लॉकडाउन की शुरुआत से ठीक पहले टीबी दिमागी बुखार का पता चला था। उनके पति एक मोची हैं और उसको नहीं पता था कि सरकारी डॉट्स सेंटरों से टीबी का मुफ्त इलाज होता है, इसलिए निजी डॉक्टरों पर हजारों रुपये खर्च किए, पर फायदा नहीं हुआ। लॉकडाउन के कारण कुछ दिक्कत के बावजूद सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने सविता को पास के डॉट्स सेंटर में एनरोल करने में मदद की और मुफ्त इलाज मिलना शुरू हो गया। सही दवा के बावजूद, उसकी हालत बिगड़ती रही और इस तरह वह अपाहिज हो गया और उसका वजन 21 किलो तक गिर गया। वह सरकारी टीबी अस्पताल में 3 महीने से अस्पताल में भर्ती थी, उसे मुफ्त इलाज और खाना मिला था। धीरे-धीरे वह ठीक होने लगी, अब उसका वजन फिर से 38 किलो तक हो गया और अब उसे सिर दर्द या मतली जैसी कोई परेशानी नहीं है।

यह गाइड बुक इन सनस्थाओं की मदद से बनाई गई है:

- Justice Ventures International www.justiceventures.org; and
- EFICOR www.eficor.org

यह क्रिएटिव कॉमन्स के तहत कॉपीराइट है, जिसका अर्थ है कि यदि आप सामग्री पसंद करते हैं, तो आप इसे किसी भी तरह से उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं जो पैसा कमाने नहीं है, जब तक आप ऊपर दिए गए 2 समूहों को काम का श्रेय देते हैं, और दूसरों को स्वतंत्र रूप से अपने काम का उपयोग करने की अनुमति देते हैं।

